श्री मधु लिमये : घोर कमी है उसकी ।

श्री रामसेवक यादव : इस देश की खेती इंद्र और इन्दिरा के बीच चौपट हो रही है । मैं जानना चाहता हूं कि छोटे किसानों को जिनके पास धन नहीं है, पानी नहीं है, उनको मुफ्त पानी देने और उनका लगान खत्म करने पर मंत्रालय विचार कर रहा है ताकि खेती की उपज बढ़ाई जा सके ।

श्री श्यामवर मिश्र : जहां तक किसानों को पानी की सुविधा देने का सवाल है इन पिछले पंद्रह वर्षों में करीब-करीब 35 मिलियन एकड़ पर और अधिक पानी दिया गया है । जहां तक उनको सस्ता या बिना पैसे लिये हुए पानी देने का सवाल है सरकार इसको नहीं मानती है क्योंकि प्रश्न यह नहीं है कि बिना पैसा पानी उनको मिले बल्कि प्रश्न यह है कि उनको पानी मिले । उसके लिए सरकार कोशिश कर रही है । किसानों को माइनर इरिगेशन, मीडियम इरिगेशन और मेजर इरिगेशन प्राजैक्ट्स से जहां आज 90 मिलियन में पानी दिया जा रहा है वहां थ्री प्लान पीरियड में 55 मिलियन में ही दिया जाता था । चौथी योजना में करीब तीस मिलियन एकड़ और सिंचाई के लिए पानी देने की व्यवस्था सरकार करने जा रही है ।

श्री रामसेवक यादव : लगान के बारे में नहीं बताया है ।

श्री श्यामवर मिश्र : लगान के बारे में ऐसी कोई सरकार की नीति नहीं है कि इसको खत्म कर दिया जाए । इसको खेती के लिए बाधक नहीं समझा जाता है ।

M/s. Bird & Co.

+

*157. **Shri Madhu Limaye:**
Shri Kishen Pattnayak:
Dr. Ram Manohar Lohia:

Will the Minister of Law be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 517 on the 18th August, 1966 and state:

(a) whether M/s. Bird and Co. and their associates had committed any violations of and offences against the Company Law;

(b) if so, whether any prosecution has been started against this firm and its associates; and

(c) the stage reached in this prosecution?

The Minister of Law (Shri G. S. Pathak): (a) As stated by the Minister in the Ministry of Finance in reply to Starred Question No. 517 the concerned companies have preferred appeals against the original adjudication order. The appeals are still pending. Facts which would constitute violations of the provisions of the Companies Act are in dispute and under scrutiny in those pending appeals. Hence, on disposal of those appeals and the facts found therein, it would be possible to ascertain if the company and their associates have committed any violation of and offences against the Company Law and to determine further necessary action.

(b) and (c). Do not arise.

श्री मधु लिमये : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने यह वादा नहीं किया था कि कस्टम के मामले में पंचों का, यानी एजुडिकेशन का, निर्णय आते ही आयकर तथा कम्पनी कानून का जो उल्लंघन हुआ है, उसके सम्बन्ध में तुरन्त कार्यवाही की जायेगी; यदि हां, तो क्या आज यह कार्यवाही इसलिए नहीं की जा रही है कि चूंकि वर्तमान वित्त मंत्री अपने इस पद को ग्रहण करने से पहले इस बर्ड कंपनी के एसोशिएट फर्म के डायरेक्टर थे ?

अध्यक्ष महोदय : बार-बार इस तरह का आरोप लगाने की क्या जरूरत है कि चूंकि किसी शख्स का उससे ताल्लुक था इसलिए कार्यवाही नहीं की जा रही है ।

श्री मधु लिमये : यह बिल्कुल सम्बन्धित है । इसमें क्या अनुचित है ? चूंकि वह इस एसोसिएट फर्म के डायरेक्टर थे, इसीलिए मैंने यह प्रश्न पूछा है । मंत्री महोदय जवाब दे सकते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है ।

Shri G. N. Dixit: Sir, I have a submission to make. Rule 41 (iii) is being repeatedly violated by the hon. Members on that side. Rule 41 (iii) reads as follows:

> "it shall not contain arguments, inferences, ironical expressions, imputations, epithets or defamatory statements;"

What the hon. Member mentioned is absolutely in violation of the provisions of this rule. I think you should ask those hon. Members who are making repeated violations of this rule in putting their supplementary questions to abjure this practice and read these rules carefully.

श्री मधु लिमये : अध्यक्ष महोदय, यह नये नये छात्र हैं, विद्यार्थी हैं, इसलिए ऐसी बातें करते हैं ।

Mr. Speaker: It is not for the first time that it has been brought to the notice of the Members that no imputations, inferences or such things should be brought in when putting a supplementary question. They ought simply to elicit information on the facts.

श्री मधु लिमये : मैं तो जानकारी ही चाहता हूं ।

Mr. Speaker: This is a clear indication. That might be done in a different manner but not in putting a supplementary question.

श्री मधु लिमये : मैं अपने प्रश्न को बदल कर पूछता हूं, जिससे आपको संतोष हो जाये ।

अध्यक्ष महोदय : मिनिस्टर साहब सवाल के पहले हिस्से का जवाब दे दें और दूसरे हिस्से का जवाब देने की जरूरत नहीं है ।

श्री मधु लिमये : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने यह आश्वासन दिया था और क्या इस आश्वासन का उल्लंघन किया जा रहा है ।

Shri G. S. Pathak: The second part of the question should be expunged from the record—

Mr. Speaker: I have not allowed him.

Shri D. C. Sharma: Then, what was the good of that hon. Member raising that point?

Mr. Speaker: I do not understand what he wants. I have not admitted that. I have said that. What else does he want?

Shri D. C. Sharma: I agree with you, Sir, but those two persons—Shri Madhu Limaye there and the hon. Member on this side—are wasting our time.

Shri G. S. Pathak: The Government will go into the question so far as the Company Law Administration is concerned after the final decision by the Board of Revenue in the appeal which has been filed against the adjudication. Now, the question in that appeal necessarily would be, whether there has been under-invoicing. Supposing in that appeal it is decided there was no under-invoicing, then there would be no question of any breach of the company law arising.

Shri Daji: My point is....

Mr. Speaker: Shri Banerjee had already risen.

Shri S. M. Banerjee: My point of order is this. I refer to rule 376 of the Rules of Procedure

Mr. Speaker: What is the rule? That is being insisted upon.

Shri S. M. Banerjee: Rule 376(2).

Mr. Speaker: That cannot be relied upon for this purpose. That does not give any substantive right of raising a point of order except when it relates to the order of the business.

Shri S. M. Banerjee: It says:

"A point of order may be raised in relation to the business before the House at the moment."

The business before the House now is Question Hour.

Mr. Speaker: No, no; he cannot raise it under that rule.

श्री मधु लिमये : मैं यह जानकारी चाहता हूं कि क्या रेवेन्यू बोर्ड के वर्तमान चेयरमैन को उनके द्वारा इस्तीफा दिये जाने के पहले ही व्यापार मंत्रालय में एडीशनल कामर्स सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है; यदि हां, तो क्या यह परम्परा के विपरीत नहीं है और बर्ड एंड कम्पनी के एजुडिकेशन में जो अपील की गई है, क्या इसका उससे सम्बन्ध है ।

श्री गोपाल स्वरूप पाठक : श्रीमान्, जिस सवाल का मैं जवाब दे रहा हूं, उससे इस सवाल का कोई ताल्लुक नहीं है ।

श्री मधु लिमये : कैसे ताल्लुक नहीं है ?

अध्यक्ष महोदय : इसका फैसला आप नहीं करेंगे । मिनिस्टर साहब को अपनी बात कहने दीजिए ।

श्री गोपाल स्वरूप पाठक : उस बोर्ड का कौन चेयरमैन है, इससे कम्पनी ला एडमिनिस्ट्रेशन को क्या ताल्लुक है ? जब सवाल यह पूछा जा रहा है कि कम्पनी ला एडमिनिस्ट्रेशन एक्शन ले रहा है या नहीं, तो मैं पहले से यह कैसे मालूम कर सकता था कि बोर्ड का कौन चेयरमैन है और कौन मेम्बर्स हैं ।

श्री मधु लिमये : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का जवाब नहीं दिया गया है । मैं आपका संरक्षण चाहता हूं । उन्होंने कहा कि सारा मामला निर्भर करता है एजुडिकेशन पर और एजुडिकेशन को अपील किसके सामने है ?—रेवेन्यू बोर्ड के सामने । यह पूरी परम्परा को खत्म किया जा रहा है । रेवेन्यू बोर्ड फिनांस मंत्रालय के मातहत आता है और उसके चेयरमैन को उन्होंने कामर्स मंत्रालय में एडीशनल सेक्रेटरी बनाया है । इसका इस केस पर असर हो रहा है, इसीलिए मैंने यह प्रश्न पूछा है ।

अध्यक्ष महोदय : श्री दाजी ।

श्री मधु लिमये : अध्यक्ष महोदय, आप इस छोटी सी बात को उनके सामने रख दीजिए कि वित्त मंत्रालय का जो एक नौकर है, उस को एडीशनल कामर्स सेक्रेटरी कैसे बना सकते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : इस वक्त यह सवाल नहीं है ।

श्री मधु लिमये : अध्यक्ष महोदय, इसके पीछे बड़ा राज है । आप समझ नहीं रहे हैं । बड़ी साजिश है, बड़ा षड़यंत्र है इन लोगों का । डेढ़ करोड़ रुपये का मामला है ।

Shri Daji: The Minister has admitted certainly by inference that there have been certain violations and offences against the Company Law committed by Bird and Company. I would like to know what complaints have been received and what action has been taken regarding violations and offences against Company Law committed by Bird and Company. How is action under the Company Law connected with possible infringe-

ment of under-invoicing and over-invoicing? That is an entirely different subject under the customs law. Why should action under Company Law be stayed till action is finalised in regard to appeals under customs law?

Shri G. S. Pathak: If there is under-invoicing, there will be wrong entries in the accounts books and the profit and loss account and balance sheet will be incorrect. Company Law Administration is concerned with the correctness of the accounts and of the balance sheet and profit and loss account. That would again depend upon whether there was under-invoicing or not. If there was no under-invoicing, the accounts would be correct.

Shri Daji: There are other complaints under the Company Law apart from accounts.

Mr. Speaker: Question Hour is over.

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

Election Broadcasts by Independent Candidates over All India Radio

*154. **Shri S. M. Banerjee:** Will the Minister of **Law** be pleased to state:

(a) whether the Independent candidates will be allowed to broadcast at the time of Fourth General Elections; and

(b) if not, the reasons therefor?

The Minister of Law (Shri G. S. Pathak): (a) No, Sir.

(b) The principal reasons are—

(i) in the first place, it is not practicable to give broadcasting facilities to individual candidates having regard to the very much limited time which may be available for this purpose;

(ii) in the second place, the object of these broadcasts on the eve of General Elections is to give an opportunity to the public to be conversant with the aims, objects, manifestos and programmes of the organized political parties and not to provide additional platform for individual candidates for electioneering purposes.

Procurement of Foodgrains

*158. **Dr. Ranen Sen:** Will the Minister of **Food, Agriculture, Community Development and Cooperation** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that procurement of foodgrains, especially rice, is lagging behind targets;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) the total quantity of rice so far procured in the current year both on Central and State accounts?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Govinda Menon): (a) and (b). In many States, specific targets of procurement were not fixed and in some they were fixed before firm estimates of current years' production were available. On the whole, the progress of procurement cannot be considered low keeping in view the serious shortfall in production during 1965-66 crop year.

(c) About 30 lakh tonnes.

Thefts at Calcutta Port

*159. **Shri Indrajit Gupta:** Will the Minister of **Transport, Aviation, Shipping and Tourism** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the volume and value of goods stolen annually from Calcutta Port are